क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
# क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 321, शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## सार समाचार

### चिदंबरम से ईडी की पूछताछ

**नई दिल्ली।** आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से बुधवार को पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चिदंबरम अपने वकील के साथ पूर्वाह्न करीब सवा ग्यारह बजे इंडिया गेट के पास जामनगर हाउस स्थित एजेंसी के कार्यालय में पहुंचे। यह पहला मौका है, जब पूर्व वित्त मंत्री से ईडी ने इस मामले में पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को मामले के जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज कराने को कहा गया था और इसके लिए उन्हें बुधवार का समय दिया गया था। ईडी ने इससे पहले एयरसेल-मैक्सिस पीएमएलए मामले में उनसे पूछताछ की थी। पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई द्वारा आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका के अनुरोध पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक 15 जनवरी तक बढ़ा दी थी। साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

### टेम्पो ने दो छात्राओं को मारी टक्कर, एक की मौत

**भागने के चक्कर में तेज रफ्तार टेम्पो भी पलटा, चालक की मौत**

**भागने के चक्कर में तेज रफ्तार टेम्पो भी पलटा, चालक की मौत**

**नई दिल्ली एजेंसी।** भलस्वां डेयरी थानांतर्गत मुकुंदपुर रेड लाइट नाले के पास एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। इनमें एक छात्रा तथा चालक शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब दो बजे आउटर रिंग रोड पर मुकुंदपुर चौक के पास बेकाबू टेंपो ने पहले तो एक छात्रा को टक्कर मारी लेकिन जैसे ही घटनास्थल पर पब्लिक दौड़ी जल्दबाजी में टेम्पो चालक ने टेम्पो को काफी तेजी से बैक कर दिया। इस दौरान टेम्पो के पीछे खड़ी एक अन्य लड़की इसकी चपेट में आ गई और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतका शिखा मुकुंदपुर में परिवार के साथ रहती थी। वह तिमारपुर इलाके के नेहरु विहार स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में 12वीं की छात्रा थी। घायल छात्रा की पहचान कंचन के रूप में हुई। आरोपी चालक ने दो छात्राओं को टक्कर मारने के बाद एक उमेश नामक राहगीर व कुछ वाहनों को अपनी चपेट में लेते हुए मौके से आजादपुर की तरफ गाड़ी लेकर हाईवे की तरफ भागा। पकड़े जाने के डर से चालक ने वाहन की रफ्तार अचानक काफी तेज कर दी, जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में जख्मी चालक को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चालक की पहचान यूपी के मैनपुरी निवासी राजन के रूप में हुई। एक अन्य मामले में आरके पुरम इलाके में बेलगाम फॉरच्यूनर गाड़ी ने स्कूटी सवार एसएसबी के दो जवानों को टक्कर मार दी। घायल अरु मय भट्टाचार्य और राजेश कुमार को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर है।

### जीसैट-7ए का सफल प्रक्षेपण

**श्रीहरिकोटा एजेंसी।** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सैन्य संचार उपग्रह जीसैट-7ए को लॉन्च पैड जीएसएलवी-एफ11 के साथ शार रेंज से बुधवार शाम 04.10 बजे प्रक्षेपित किया। जीएसएलवी-एफ 11, 26 घंटे की उलटी गिनती के बाद अपनी 13वीं उड़ान में दूसरे लॉन्च पैड से आकाश की ओर प्रक्षेपित किया गया। इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवान सहित वैज्ञानिक मिशन नियंतण्रकेंद्र से इसका प्रक्षेपण देख रहे थे। यह एक रिकॉर्ड है कि 2018 में इसरो ने सात सफल प्रक्षेपण किए हैं। इसरो की इस सफलता पर वायुसेनाध्यक्ष बीएस धनोआ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रक्षेपण से वायुसेना की नेटवर्किंग क्षमता मजबूत होगी। धनोआ ने कहा कि यह हमारी नेटवर्किंग क्षमताओं में जबरदस्त उछाल है।

### कमलनाथ के इस्तीफे की मांग को लेकर बग्गा का अनशन जारी

**नई दिल्ली।** राजधानी में 1984 सिख दंगों के आरोपी एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बर्खास्तगी को लेकर बेमियादी अनशन पर बैठे प्रदेश भाजपा प्रवक्ता तेजेंद्र सिंह बग्गा का अनशन बुधवार तीसरे दिन भी जारी रहा। बग्गा के इस अनशन को लगातार समर्थन मिल रहा है। बुधवार को भाजपा सांसद महेश गिरी एवं दिल्ली सिख प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने अनशन स्थल पर जाकर बग्गा को नैतिक समर्थन दिया।

*मुंबई में बुधवार को अपने नवजात पुत्र इज्हान मिर्जा मलिक के साथ पहुंचीं भारतीय बैडमिंटन स्टार सानिया मिर्जा।*

### लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर बाइक सवार युवक को लूटा

**सुलतानपुर।** सुलतानपुर जिले के भदैया कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित महानपुर गांव के पास बहन के घर से निमंत्रण खाकर घर वापस आ रहे युवक को बदमाशो ने लिफ्ट मांग कर रोक लिया। मारपीट कर नगदी छीन ली। पीछे से कार सवार लोगों के पहुंचने पर बदमाश युवक को छोड़कर भाग निकले।

कोतवाली देहात अन्तर्गत अभियाकला झलियहवा गांव निवासी करिया (32) पुत्र बृजलाल मंगलवार को अपनी बहन के यहां धम्मौर थाने के रसूलपुर भांई गांव गए थे। वहां से बुधवार को देर शाम बाइक से वापस आ रहे थे। लखनऊ-वाराणसी हाईवे मार्ग पर कोतवाली देहात के महानपुर गांव के पास साल ओढकर खडे एक युवक ने उससे लिफ्ट मांगी तो उसने बाइक रोक दिया। युवक के रूकते ही सड़क के किनारे गड्ढे से निकलकर तीन और बदमाश उसके पास पहुंचे।

असलहा लगाकर बीस हजार रुपये की मांग करते हुए युवक की जेब और डिग्गी की तलाशी लेने लगे। जेब रखा छह सौ रुपये छीन लिये।

बदमाशो ने विरोध करने पर और रुपये न होने से इंकार करने पर उसके सिर एवं गर्दन पर हाकी मारकर घायल कर दिये। इसी बीच पीछे से आ रही कार को देखकर बदमाश वहां से भाग निकले। इसके बाद करिया के रोकने पर कार पर सवार लोगों ने करिया को खून से लथपथ देखकर घटना की जानकारी ली। उसके कहने पर उसे हनुमानगंज बाजार ले आये। उसके परिजन युवक को सीएचसी लंभुआ मे भर्ती कर इलाज करा रहे है । हाईवे पर सरेशाम हुई घटना से लोगो मे दहशत है। कोतवाली देहात पुलिस ने बताया की जानकारी मिली है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

## किसानों के सवाल पर सपा, बसपा व कांग्रेस ने विधानसभा से किया वार्कआउट

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा, बसपा व कांग्रेस ने उर्वरक की कमी व बढ़ी कीमतों को लेकर सत्ताधारी भाजपा को घेरने की कोशिश की। इन दलों के सदस्यों ने किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट किया। विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में बसपा के रितेश पाण्डेय ने उर्वरक की उपलब्धता और इसकी कीमत में बढोतरी का सवाल उठाया। इस पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पहले की सरकारों में उर्वरक के लिए किसानों को लाइन लगानी पड़ती थी और उसके लिए ज्यादा दाम देने पड़ते थे। अब उर्वरक की कहीं कमी नहीं है। यह किसानों को आसानी से उपलब्ध है। बसपा दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि उर्वरकों की कीमत काफी बढी है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या वह किसानों को राहत देने के लिए उर्वरक के दाम कम कराएगी। बाद में सरकार के जवाब से असंतुष्ट बसपा ने सदन से वाकआउट किया। इसके बाद सपा के नरेंद्र वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के मुददे पर गंभीर नहीं है। इसी के साथ ही सपा के सदस्यों ने भी वाकआउट किया। इसके बाद कांग्रेस सदस्य भी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट कर गये।

**मंदिरों को ध्वस्त किये जाने के मुद्दे पर कांग्रेस का वाकआउट**

प्रदेश सरकार द्वारा काशी विश्वनाथ गलियारे के नाम पर वाराणसी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सदस्यों ने आज विधानसभा से वाकआउट किया।

सदन जैसे ही 11 बजे बैठा, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने नियम 311 के तहत इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 125 करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है।

वह इस मुद्दे पर चर्चा चाहते थे लेकिन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि पहले प्रश्नकाल हो जाने की बात कहते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद वे सदन से बहिर्गमन कर गये।

## फल, मसाला और फूल की खेती कर ऐसे लाभ कमाएं किसान

**सुलतानपुर।** सुलतानपुर जिला औद्यानिक मिशन की ओर से कृषक गोष्ठी के पहले दिन वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती की नई तकनीकि की जानकारी दी। सब्जी, फल, मसाला व फू ल की खेती वैज्ञानिक विधि से करने व उद्यान विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दस प्रगतिशील किसानों को नगद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पर्यावरण पार्क में उद्यान विभाग की ओर से आयोजित कृषक गोष्ठी की शुरुआत उपजिलाधिकारी प्रणव सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर की। उपनिदेशक उद्यान वाहिद अली ने किसानों को जनपद में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने औद्यानिक कार्यक्रम के बारे में बताया। गोष्ठी में शामिल भाजपा जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह छंगे, भाजपा नेता सीताशरण त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी डीआर विश्वकर्मा ने मेले में लगे स्टालों का अवलोकन कर किसानों के उत्पादों को देखा।

### पूर्व नौकरशाहों ने लिखा खुला पत्र पूर्व नौकर सुमित का परिवार मिला योगी से

## बुलंदशहर हिंसा राजनीतिक साजिश

**एसआईटी जांच में गोकशी के चार आरोपी निदरेष चार ने किया कोर्ट में सरेंडर**

**बुलंदशहर।** स्याना हिंसा के आरोपी चार और लोगों ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। सरेंडर करने वालों में ग्राम महाव निवासी हरेन्द्र, टिंकू, गुड्डू तथा ग्राम चिंगरावठी निवासी छोटे उर्फ अविनाश हैं। कानून की गिरफ्त में अभी तक 25 आरोपी आ चुके हैं। इसके अलावा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। स्याना हिंसा बवाल मामले में घटना के दो दिन बाद गोकशी के आरोप में जेल भेजे गये चार युवक एसआईटी जांच में निदरेष पाये गये हैं। इस मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज की तहरीर पर गोकशी के आरोप में सात के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने चार नामजदों नया गांव निवासी साजिद व सरफुद्दीन, ग्राम खेलिया कल्याणपुर निवासी बन्ने खान, दिल्ली दरवाजा औरंगाबाद निवासी आसिफ को गत 4 दिसम्बर को जेल भेज दिया था। एसआईटी जांच में उक्त के विरुद्ध कार्रवाई गलत और उपरोक्त को निदरेष पाया गया है। बताया जाता है कि पुलिस ने अब 2/3 दिसम्बर की रात में महाव के जंगल में गोकशी करने के आरोप में तीन आरोपियों नदीम, रईस व काला कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या से क्षुब्ध कई पूर्व नौकरशाहों ने एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य में इस घटना से पहले और बाद में उत्पन्न तनाव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पत्र में लिखा है कि 3 दिसम्बर 2018 को हुई हिंसक घटना के दौरान पुलिस अधिकारी की हत्या राजनीतिक द्वेष की दिशा में अब तक का एक बेहद खतरनाक संकेत है। इससे पता चलता है कि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में शासन पण्राली के मौलिक सिद्धांतों, संवैधानिक नीति और मानवीय सामाजिक व्यवहार तहस-नहस हो चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एक पुजारी की तरह धर्मांधता और बहुसंख्यकों के प्रभुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसे सहन नहीं किया जा सकता। सभी नागरिकों को नफरत की राजनीति और विभाजन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इस पत्र में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने में नाकाम रहने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस घटना का संज्ञान लेते हुए न्यायिक जांच का अनुरोध भी किया गया है।

खुला पत्र जारी करने वालों में श्याम सरन, सुजाता सिंह, एनसी सक्सेना, अरुणा रॉय, जूलियो रिबेरो, नजीब जंग और हर्ष मंदेर सहित कुल 83 पूर्व नौकरशाह शामिल हैं।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने वाले विपक्ष की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि बुलंदशहर की घटना उन लोगों का ''राजनीतिक षडयंत्र' था, जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि बुलंदशहर हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर सहित दो सुमित का परिवार मिला योगी से लखनऊ।

## लोकसभा सीट ही नहीं, ND और LJP के बीच तल्खी की ये भी है 'वजह'

**नई दिल्ली।** बिहार की राजनीति बीते लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के लिए आसान नहीं रही है। विधानसभा चुनाव के बाद ही जीतनराम मांझी ने साथ छोड़ दिया था।

उसके बाद जदयू साथ आया तो रालोसपा की नाराजगी बढ़ गई और आखिर में उसने भी साथ छोड़ दिया। अब लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें ज्यादा सीटें नहीं चाहिए। उधर, लोजपा के बिहार अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी को 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा कर लेने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पहले से कम सीटें उन्हें मंजूर नहीं। जदयू भी नए फार्मूले पर भाजपा की छह संसदीय सीटें ले रहा है। कमजोर पड़ रही बीजेपी के सामने लोजपा ने भी साथ छोड़ने की परोक्ष धमकी दे दी है।

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी इस मामले पर रामविलास पासवान से बात करेगी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर लोजपा के अल्टीमेटम पर काम नहीं करेगी।

**राज्यसभा सीट भी एक वजह :**

सूत्रों के अनुसार, लोजपा का दवाब राज्यसभा सीट के लिए ज्यादा है। वह अपने नेता रामविलास पासवान को राज्यसभा में लाना चाहती है।

भले ही लोकसभा में उसे एक-दो सीट कम मिले। भाजपा फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान का ट्वीट भी इसी दबाब का हिस्सा माना जा रहा है

हालांकि, बीजेपी का कहना है कि सीटों के बंटवारे को लेकर इस तरह के बयान आते रहते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है।

भाजपा अंदरूनी तौर पर लोजपा के रुख को लेकर सशंकित है। रामविलास पासवान माहौल देखकर पाला बदलते रहे हैं और 1996 के बाद एक बार (2009) को छोड़कर हर सरकार में मंत्री रहे हैं। चाहे वह भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या तीसरे मोर्चे की। लोकसभा चुनावों से पहले तीन राज्यों की सरकारें गंवाने से भाजपा का पक्ष कमजोर पड़ रहा है। सहयोगी दल इसी का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं।

### 'बुलंदशहर हिंसा' पर बोले नसीरुद्दीन शाह

## 'गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है, मुझे अपने बच्चों के लिए डर लगता है'

**नई दिल्ली एजेंसी।** बॉलीवुड के वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में देश के बदलते माहौल और बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता जताई है। ये वीडियो इंटरव्यू 'कारवां ए मोहब्बत' नाम के यू-ट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। जहां नसीरुद्दीन शाह ने देश में हो रही मॉब लिचिंग जैसी घटनाओं पर खुलकर अपनी बात रखी हैं। खास बात ये है कि नसीरुद्दीन शाह ने इस इंटरव्यू में कहा- 'हमने बुलंदशहर हिंसा में देखा कि गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है न कि पुलिस ऑफिसर की मौत को, मुझे अपने बच्चों के लिए बेहद डर लगता है कि अगर कही मेरे बच्चों को भीड़ ने घेर लिया और उनसे पूछा जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? मेरे बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। पूरे समाज में जहर फैल चुका है।' आगे वीडियो में सुनिए ये पूरा इंटरव्यू और जानिए वो खास बातें जो नसीरुद्दीन शाह ने यहां कहीं...

**'ये हमारा घर है कौन निकाल सकता है हमे यहां से...'**

नसीरुद्दीन शाह ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि इस जिन्न को बोतल में बंद करना मुश्किल होगा। लोगों को खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथ में लेने की। लेकिन मुझे इन सभी बातों से डर नहीं लगता बल्कि गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि हर इंसान को इन बातों से डर नहीं लगना चाहिए बल्कि गुस्सा आना चाहिए। और ये हमारा घर है कौन निकाल सकता है हमे यहां से।

**बच्चों को नहीं दी मजहबी तालीम...**

नसीरुद्दीन शाह ने अपने बच्चों को लेकर भी चिंता जाहिर की- मुझे अपने बच्चों के लिए बेहद डर लगता है कि अगर कही मेरे बच्चों को भीड़ ने घेर लिया और उनसे पूछा जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान?

मेरे बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी है। क्योंकि अच्छाई और बुराई का मजहब से कोई मलतब नहीं है। बता दें कि 3 दिसंबर को बुलंदशहर हिंसा में पुलिस इंसपेक्टर सुबोध कुमार सिंह को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरा विवाद गोकशी का था।

## संपादकीय

जब नोटा का विकल्प आया था, तब यही कहा गया था कि यह सुविधा प्रत्याशियों को खारिज करने का जरिया बनेगी और पार्टियों को अपने उम्मीदवारों का सही चयन करने को बाध्य भी करेगी, लेकिन अब नोटा न सिर्फ पार्टियों का भविष्य तय करने लगा है, बल्कि बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हैरत में डाल रहा है। ऐसा मध्यप्रदेश समेत पांच राज्यों के चुनाव ने साबित भी कर दिया है।

# नोटा भी तय करने लगा है नियति

कई संगठनों ने चुनावों में मतदाताओं को तीसरा विकल्प देने की कानूनी लड़ाई लंबे समय तक लड़ी। पहली नजर में यह मांग तर्कसंगत लगती थी कि यदि किसी मतदाता को कोई उम्मीदवार पसंद न हो उस स्थिति में भी उसे उन्हीं में से एक उम्मीदवार को मत देने के लिए मजबूर करना लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए एक विकल्प दिया गया, नोटा। इसे नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं कहते हैं। जिस समय यह विकल्प मिला शायद ही किसी ने सोचा हो कि यह चुनाव में जीत का कारण भी बन सकता है। यही सोचा गया कि इससे यह पता चल सकेगा कि किसी क्षेत्र में कितने लोगों के बीच उम्मीदवार आलोकप्रिय थे या कितने लोगों ने किसी न किसी कारण उम्मीदवारों या चुनावों के प्रति नाराजगी प्रकट की। इस आधार पर ही यह टिप्पणी की जाने लगी कि नोटा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें दिया गया वोट व्यर्थ जाता है। जब कोई उम्मीदवार जीतता व हारता नहीं तो पार्टियां भी इससे गंभीरता से नहीं लेतीं। किंतु अब स्थिति बदलने लगी है। वास्तव में इससे आगे चलकर नोटा अब जीत और हार का भी फैसला करने लगा है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में नोटा फिर इसी कारण चर्चा में है इसने परिणामों को प्रभावित किया है।

तेलंगाना, मिजोरम एवं छत्तीसगढ़ में नोटा का प्रभाव इसलिए नहीं दिखा क्योंकि यहां जीतने हारने वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर ज्यादा था। तेलंगाना में नोटा को दो लाख 24 हजार 709 मत मिले जो कुल मतों का केवल 1.1 प्रतिशत था, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति एवं कांग्रेस गठबंधन के बीच 14.1 प्रतिशत का अंतर है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच 10 प्रतिशत मतों का अंतर है और यहां नोटा को केवल दो प्रतिशत मत मिले। किंतु दो प्रमुख राज्यों राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के चुनाव परिणामों पर इसने उलटफेर करने में भूमिका निभाई है। प्रदेश स्तर पर देखें तो राजस्थान में दोनों पार्टियों के बीच मतों का अंतर केवल .3 प्रतिशत है। यहां नोटा को कुल 1.3 प्रतिशत मत मिले हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि इसने किस तरह परिणाम को प्रभावित किया होगा। कांग्रेस और भाजपा के बीच केवल एक लाख 77 हजार 966 मतों का अंतर है। नोटा ने अपने हिस्से चार लाख 67 हजार 781 मत गटक लिए। उपर की चार पार्टियों को छोड़ दें तो अन्य सभी पार्टियों को नोटा से काफी कम मत मिले हैं।

हालांकि मध्यप्रदेश में तो हारने के बावजूद भाजपा का मत कांग्रेस से थोड़ा ज्यादा है। कांग्रेस को एक करोड़ 55 लाखर 95 हजार 153 यानी 40.9 प्रतिशत तथा भाजपा को 1 करोड़ 56 लाख 42 हजार 980 यानी 41 प्रतिशत वोट मिले। इस तरह भाजपा को 47 हजार 827 मत यानी .1 प्रतिशत मत ज्यादा मिले। यहां नोटा के हिस्से पांच लाख 42 हजार 295 यानी 1.4 प्रतिशत मिले। मध्यप्रदेश में साल 2013 में नोटा को छह लाख 52 हजार 116 वोट मिले थे। इस तरह करीब 15 प्रतिशत कम लोगों ने इस बार नोटा का बटन दबाया। किंतु, पिछली बार सीटों और वोटों में इतना अंतर था कि नोटा पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। यही स्थिति राजस्थान की थी। वहां पिछली बार 5 लाख 89 हजार 923 लोगों ने नोटा दबाया था जो कि इस बार से 20 प्रतिशत ज्यादा था। दोनों राज्यों में कांटे की टक्कर न के बराबर थी। इस बार कांटे की टक्कर में इनकी भूमिका रही। हालांकि पछली बार छत्तीसगढ़ में नोटा ने खेल किया था। दोनों पार्टियों के बीच केवल 97 हजार मतों का अंतर था और नोटा में चार लाख एक हजार 58 मत पड़े। आने वाले समय में ज्यादा विस्तार से इसका अध्ययन हो पाएगा।

राजस्थान में 15 विधानसभा क्षेत्रों में विजयी रहे उम्मीदवारों की जीत-हार के अंतर से ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं। दोनों पार्टियों को इसने बराबर प्रभावित किया है। ये क्षेत्र हैं, घाटोल, चौहटन, पचपदरा, आसिंद, बूंदी, पीलीबंगा, चौमू, मालवीय नगर, पोकरण, खानपुर, खेतड़ी, मकराना, मारवाड़ जंक्शन, दांतारामगढ और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जहां उम्मीदवार की जीत के अंतर से ज्यादा नोटा का इस्तेमाल किया गया। मध्यप्रदेश में 25 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां नोटा ने प्रत्याशियों का जीत हार तय किया है। 17 में भाजपा हारी तथा आठ में कांग्रेस। यानी दोनों पार्टियों को क्षति हुई लेकिन भाजपा को ज्यादा हुई है। दमोह, गन्नौर, इंदौर-5, जबलपुर उत्तर, ग्वालियर दक्षिण, जावरा, जोबट, मांधाता, नागौद, नेपानगर, पेटलावद, राजनगर, राजपुर, सुवासरा, टिमरनी, बिओरा, गरोथ, सुवासरा, नेपानगर, मान्धाता, कोलारस, जओरा, गुनौर, चंदला और बीना विधानसभा सीटें इनमें शामिल हैं। इस अंकगणित के आधार पर यह कहने में संकोच नहीं है कि दोनों राज्यों के वर्तमान राजनीतिक हालात नोटा के कारण पैदा हुए हैं। नोटा नही होता तो परिणाम कुछ और होते।

यह पहली बार नहीं है। इसी वर्ष मई में हुए कर्नाटक चुनावों में छह विधानसभा सीटों पर भाजपा कांग्रेस से जितने मतों से पराजित हुई उससे ज्यादा मत नोटा को पड़े थे। नोटा का विकल्प नहीं होता तो आज कर्नाटक में भाजपा की सरकार होती। इसके पूर्व गुजरात में पांच लाख 51 हजार 414 यानी कुल 1.8 प्रतिशत वोट नोटा के हिस्से गए। वहां भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे स्थान पर नोटा ही था। करीब 10 विधानसभा क्षेत्रों में वहां भी नोटा ने उम्मीदवारों की नियति बदल दी। अब चूंकि जीत हार के अंतर में नोटा की ओर लोगों का ध्यान गया है इसलिए इस दृष्टि से इसका अध्ययन होने लगा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया तो उनने केवल उम्मीदवारों, पार्टियों या किसी अन्य मुद्दे को लेकर अपना असंतोष प्रकट करने के रूप में ही इसे लिया होगा। उस समय 60 लाख लोगों ने नोटा का बटन दबाया जो कुल वोट का 1.1 प्रतिशत था। ये 21 पार्टियों को मिले वोटों से अधिक था। इसका कुछ तो निष्कर्ष निकलता था। पर तब इसे गंभीरता से शायद ही किसी ने लिया होगा। हालांकि उस समय भी सबसे ज्यादा तीन प्रतिशत लोगों ने पुडुचेरी में नोटा का बटन दबाया था। उसके बाद 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा को 9 लाख 47 हजार 276 वोट मिले जो कुल पड़े वोट का 2.5 प्रतिशत था। वहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कुल 8 लाख 64 हजार 856 वोट मिले थे।

तो अब नोटा को कैसे विश्लेषित किया जाए? कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा परिणाम आने के बाद जब यह खबर आई कि नोटा के कारण ऐसा हुआ है तबसे इसकी ओर आम मतदाताओं का भी ध्यान गया है। जब संसद ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटा तो इससे एक तबके के अंदर गुस्सा पैदा हुआ। उसमें सभी पार्टियों की भूमिका थी, पर निशाने पर केंद्र सरकार थी। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चला कि नोटा दबाकर पार्टियों के खिलाफ गुस्सा प्रकट किया जाए। अलग-अलग राज्यों में कुछ लोगों ने संगठन बना लिया। नोटा यात्राएं निकाली गईं। कुछ संगठनों ने भी लोगों के बीच जाकर प्रचार किया कि नोटा बटन दबाकर विरोध जताया जाए। अगर इसे एक प्रवृत्ति मान लिया जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी मत नोटा के पक्ष में जा सकता है। इस तरह नोटा की यात्रा कहां से चली और कहां पहुंच रही है। क्या यह सही दिशा है? यह प्रश्न इसलिए गंभीर है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के विरोध में इसका उपयोग होना समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। कल कोई वर्ग अपने निहित स्वार्थ के लिए नोटा का इस्तेमाल कर सकता है। जाहिर है, नोटा को लेकर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है।

**अवधेश कुमार**
(वरिष्ठ पत्रकार)

## विचार

# सरोगेसी पर सख्ती जरूरी

पिछले कुछ सालों में चिकित्सा बाजार में सरोगेट मदर का धंधा जिस कदर फल-फूल रहा था, उसमें चुपचाप पल रहे कुछ अमानवीय पहलुओं की अनदेखी हो रही थी। अब जबकि सरकार ने कानून पास कर दिया है, तो उम्मीद करनी होगी कि गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी।

सरोगेसी रेगुलेशन बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इस कानून के जरिए सरोगेट महिलाओं के शोषण को रोकना अहम मकसद है। इस बिल के जरिए प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण करते हुए सरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से सरोगेसी की इजाजत दी गई है। इस कानून के तहत कमर्शियल सरोगेसी पर पूरी तरह बैन होगा। यानी बच्चा चाहने वाले माता-पिता, उन्हें कोख किराए पर देने वाली महिला को सिर्फ दवाइयों और अस्पताल के खर्चे के अलावा कुछ और नहीं दे सकते। बिल के प्रावधानों के मुताबिक कोख उधार देने वाली महिला बच्चा चाहने वाले माता-पिता की करीबी रिश्तेदार ही होनी चाहिए। बिल के प्रावधानों के मुताबिक कोई भी महिला अपने गैमीट (एग/अंडाणु) देकर या फिर बच्चे को अपनी कोख में पाल कर एक बार से अधिक सरोगेसी में मदद नहीं कर सकती। बता दें कि अपनी कोख को किराए पर देते हुए किसी और के लिए वारिस पैदा करने को ही सरोगेसी कहते हैं।

हाल के दिनों में दुनियाभर से लोग सरोगेट मांओं की तलाश में भारत आ रहे थे। ऐसे में अपनी कोख को किराए पर देने वाली महिलाओं की कई मायनों में अनदेखी आशंका थी। जिसके मद्देनजर अब संसद में सरोगेसी बिल पास किया गया है। बीते साल ही हैदराबाद के अस्पताल से 46 सरोगेट महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान गैरकानूनी तरीके से अस्पताल में बंधक बनाने की खबर सामने आई थी। इनमें अधिकतर महिलाएं दिल्ली, दार्जलिंग, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के गरीब तबकों से आती थीं। इन्हें महज 2-3 लाख रुपए के एवज में अपनी कोख को किराए पर रखने के लिए बाध्य किया गया था। चिकित्सा बाजार में सरोगेट मदर का धंधा जिस कदर फल-फूल रहा था, उसमें अमानवीय पहलुओं की अनदेखी हो रही थी। विडंबना यह थी कि कारोबार की शक्ल ले चुके सरोगेसी को रोकने कानूनी स्तर पर कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सरकार ने जो फैसला लिया है, उसे सकारात्मक पहल कहा जा सकता है।

दरअसल, भारत में सरोगेसी का जो ढांचा बन गया है उसमें किसी दंपति के लिए इस पद्धति से बच्चा हासिल करना इतना आसान और कम खर्च में संभव हो रहा था कि इस मकसद से विदेशों से यहां आने वाले लोगों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब सरोगेसी का नियमन नहीं होने की सबसे ज्यादा मार सेरोगेट मदर पर पड़ने की बात उठाई जाती थी, तो यह दलील देकर वह दबा दी जाती रही कि इससे गरीब महिलाओं की कुछ मदद हो जाती है। यह अपने आप में एक संवेदनहीन तर्क है कि किसी की मजबूरी और त्रासदी का हल कुछ रकम अदा करना भर मान लिया जाए। वैसे, अब भी ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है, जो कानून को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़कर पेश करेगा। अतः यह सभी की जिम्मेदारी है कि कानून का प्रचार-प्रसार करें।

# मिल सकती है किसानों को राहत

वित्त वर्ष-2019 की दूसरी तिमाही में कृषि और सहयोगी गतिविधियों में 3.8 फीसदी की दर से वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 2.6 फीसदी की दर से वृद्धि हुई थी। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 3.8 फीसदी की वृद्धि दर में मुख्य योगदान संबंद्ध गतिविधियों जैसे, पशुपालन, वानिकी और मछली पालन का रहा। इन क्षेत्रों में 6.7 फीसदी की दर से वृद्धि हुई है। फसल उत्पाद, जिसमें सब्जियां व फल शामिल हैं में 0.5 फीसदी की दर से वृद्धि हुई। फिलहाल, कृषि क्षेत्र विविध समस्याओं से जूझ रहा है। चिंता कृषि उपज की कम कीमत को लेकर भी है। उदाहरण के तौर पर कृषि उपज की कीमत वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में (-1.0 फीसदी) थी। कृषि डिफ्लेटर में गिरावट की प्रवृत्ति कृषि क्षेत्र में व्याप्त दुर्दशा की ही पुष्टि करती है। बाजार में अधिकांश कृषि उत्पादों की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी कम है। ऐसी नकारात्मक स्थिति तब है जब सरकार ने विगत चार सालों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, विविध सिंचाई कार्यक्रम, एमएसपी को 1.5 गुना करने जैसे उपायों के माध्यम से किसानों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की है।

वित्त वर्ष-2019 की दूसरी तिमाही में कृषि और सहयोगी गतिविधियों में 3.8 फीसदी की दर से वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 2.6 फीसदी की दर से वृद्धि हुई थी। कृषि अग्रिम में कम वृद्धि यह बताती है कि कृषि गतिविधियों में सुस्ती की स्थिति बनी हुई है। अतः हमें किसानों की दुर्दशा सुधारने के लिए दूसरे उपायों पर भी ध्यान देना होगा। इन उपायों में हम पशुधन को बढ़ावा दे सकते हैं।

कृषि अग्रिम में कम वृद्धि यह बताती है कि कृषि गतिविधियों में सुस्ती की स्थिति बनी हुई है। कुछ बैंकों के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च-2018 से सितंबर-2018 की तिमाहियों में सकल कृषि अग्रिम में एनपीए की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इधर, कुछ राज्यों ने चुनाव को ध्यान में रखकर कृषि कर्ज को माफ करने की नीति अपनाई है, जिससे एनपीए की स्थिति और भी खराब हो गई है। कर्ज माफी की वजह से ईमानदार किसान कृषि कर्ज चुकाने से परहेज करने लगे हैं। पिछले साल गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि बेहतर हुई थी, लेकिन खाद्य ऋण में वृद्धि अभी भी कमजोर बनी हुई है। गैर-खाद्य ऋण में इस वित्त वर्ष में 3.9 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि खाद्य ऋण में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान वृद्धि महज 14 हजार 900 करोड़ रुपए की हुई। गैर-खाद्य ऋण के भीतर भी कृषि अग्रिम में वृद्धि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कम रहने की उम्मीद है।

हालांकि, सितंबर, 2018 में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई थी। सितंबर-2018 में इसमें वर्ष दर वर्ष के आधार पर मार्च-2018 के 3.8 फीसदी के मुकाबले 5.8 फीसदी की वृद्धि हुई। नाबार्ड संस्था ने हाल ही में एनएएफआईएस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, जिसके मुताबिक कृषि क्षेत्र में दी जा रही मजदूरी कम है, जबकि पशुधन, जिसमें वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर ठीक रही है और चालू वित्त वर्ष में इसमें 8 फीसदी की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। पशुओं की आबादी के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। दुनिया में कुल आबादी की लगभग 57 फीसदी भैंस भारत में पाई जाती है। भारत में पशु आबादी दुनिया में पशुओं की कुल आबादी का 15 फीसदी है। अगर भारत में पशुपालन पेशेवर तरीके से किया जाता है तो किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, किसानों की कृषि पर ज्यादा निर्भरता होने की वजह से उत्पन्न होने वाली जोखिमें भी कम हो सकती हैं। किसानों को हर साल मानसून की अनिश्चितता से होने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। दरअसल, आज भी देश के किसानों को हर साल सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है।

पशुधन से आय बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देसी नस्ल की गायों एवं भैंसों को पालने की प्रवृति को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इनके दूध में ए-2 ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ए-2 बीटा-केसिन प्रोटीन है, जो दूध को स्वस्थ और पौष्टिक बनाता है। भारत की अधिकांश देसी गायों एवं भैंसों में ए-2 एलील जीन पाया जाता है। दुनिया भर में ए-2 दूध की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। दूध में ए-2 जीन भारत के किसानों के लिए अधिक आय अर्जित करने के अवसरों का सृजन करता है। भारत को चाहिए कि वह इस क्षेत्र में अनुसंधान करे और ए-2 जीन आधारित दूध का अधिक से अधिक निर्यात करे। भारत में ए-2 दूध की मांग को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील के मेन्यू में इसे शामिल किया जाना चाहिए। इस काम से 15.83 मिलियन किसानों को हर साल 7000 रुपए अतिरिक्त आय होगी। ऐसे पहल से छोटे और सीमांत किसान भी इस तरह के नस्लों की गायों को पालने के प्रति प्रोत्साहित हो सकते हैं। इन फायदों को दृष्टिगत करते हुए ब्राजील में भारतीय देसी गायों को पाला जा रहा है। वहां, भारतीय गिर नस्ल के गाय प्रति दिन 70 लीटर से अधिक दूध दे रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील आज भारत के देसी गायों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।

सरकार ने किसानों की सहायता के लिए एफपीओ का गठन किया है, जिसका एकमात्र मकसद किसानों को उपलब्ध संसाधनों से करना है। एफपीओ सहकारी और निजी कंपनियों के बीच हाइब्रिड के रूप में काम करता है। यह सरकारी एजेंसियों के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कृषि वस्तुओं की खरीद में उप एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऐसी कंपनियां थोक में उत्पाद खरीदती हैं और उन्हें सदस्यों को उपलब्ध कराती हैं। यह सदस्यों से उत्पाद खरीदकर संगठित तरीके से विपणन करने का भी काम करता है। साथ ही, बैंकों के साथ तालमेल बनाकर सदस्यों को कर्ज भी उपलब्ध कराने का काम भी यह कर रहा है। किसानों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र में 2115 करोड़ रुपए की लागत से कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (स्मार्ट) की पहल की गई है, जिसका उद्देश्य नये किसानों एवं नए बाजारों को विकसित करना है। तेलंगाना सरकार किसानों की आय में इजाफा करने के लिए रायथु बंधु नाम से एक योजना चला रही है। इसके तहत 58.33 लाख किसानों को प्रति एकड़ हर फसली मौसम में 4 हजार रुपए सहायता के तौर पर उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में इस योजना के मद में 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किया है।

यह अपनी तरह की पहली योजना है, जिसमें नकदी का भुगतान किसानों को सीधे किया जा रहा है। अगर यह योजना पूरे भारत में लागू की जाती है तो 2.7 लाख करोड़ रुपए का कुल वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ने का अनुमान है। यह अनुमान सभी राज्यों में बुआई वाली भूमि के आधार पर आधारित है। किसानों की आय बढ़ाने वाली इस योजना का विस्तार बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों में किये जाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ हो सके। कहा जा सकता है कि आज कृषि क्षेत्र कृषि उपज की कम होती कीमत और कृषि उत्पादों का प्रभावी विपणन नहीं होने की समस्या से जूझ रहा है। लिहाजा, दूध उत्पादन बढ़ाने, एफपीओ योजना का विस्तार करने, कृषि आय को बढ़ाने आदि की ओर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। किसानों की दशा सुधारे बिना हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अतः किसानों की सुध लेनी ही होगी।

**सतीश सिंह**
(वरिष्ठ पत्रकार)

## ट्विटर

सरोगेसी कानून की आज के समय में जरूरत थी। गरीब महिलाओं का जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, उसे रोकना सरकार का कर्तव्य है। अब शोषण नहीं होगा।

**मेनका गांधी, केंद्रीय मंत्री**

सरकार ने सरोगेसी को लेकर जो कानून पास किया है, उसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए, तभी पूरी कवायद का असर दिखेगा और डर बैठेगा।

**कोंकणा सेन, अभिनेत्री**

## सत्यार्थ

# सीखने की जिज्ञासा

यूनानी दार्शनिक प्लेटो के घर रोज ही विद्वानों का जमावड़ा लगता था। वे कुछ न कुछ नया जानने के लिए उनके पास आया करते थे। फिर भी प्लेटो स्वयं को कभी ज्ञानी नहीं मानते थे और सदैव कुछ नया सीखने में लगे रहते थे। कई बार तो वे छोटे-छोटे बच्चों व नवयुवकों से भी कुछ सीखने के लिए उनमें घुल- मिल जाते थे। एक दिन उनके परम मित्र ने उनसे पूछा- आपके पास दुनिया के एक से बढ़ कर एक विद्वान अपनी जिज्ञासाएं लेकर आते हैं व आप उनके सवालों के तार्किक जवाब

देकर उनकी जिज्ञासा शांत भी कर देते हैं। वे अपने सवालों का जवाब पाकर स्वयं को धन्य समझते हैं, पर आपकी एक बात मेरी समझ में नहीं आती। प्लेटो बोले- कहो मित्र, तुम्हें किस बात का समाधान चाहिए। तब मित्र ने कहा- दुनियाभर के प्रतिष्ठित तर्कशास्त्रियों में आपकी गिनती होती है, तो भी आप दूसरों से शिक्षा ग्रहण करने तथा कुछ नया सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि आप को आम आदमी से सीखने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। आप तो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, आप को सीखने की भला क्या जरूरत है? कहीं आप लोगों को खुश करने के लिए उनसे सीखने का दिखावा तो नहीं करते हैं? मित्र के इस भोलेपन पर प्लेटो जोर से हंसे। फिर बोले- हरेक के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज है, जो दूसरे के पास नहीं है। अतः हर किसी के भीतर हर किसी से सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति दूसरों से सीखने में झिझक महसूस करेगा, तब तक वह सीखने से वंचित ही रहेगा। तात्पर्य यह है कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, पर सीखने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इस लिए उसे कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए।

**विनोद कुमार यादव**

## सार समाचार

### अमेरिका : इलिनोइस में करीब 700 पादरियों पर यौन शोषण का आरोप

शिकागो। अमेरिका के इलिनोइस राज्य में करीब 700 पादरियों पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप है, जो इससे पहले कैथॉलिक चर्च की ओर से बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा है। अमेरिका के मध्यपश्चिमी राज्य के शीर्ष अभियोजक ने यह खुलासा किया है।

इलिनोइस की अटॉर्नी जनरल लीसा मैडिगन ने बुधवार को कहा कि चर्च ने ऐसे पादरियों की संख्या 185 बताई थी, लेकिन उनके कार्यालय की जांच में यह संख्या काफी कम पाई गई है।

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की ओर से जारी बयान में शोषण के आरोपों से निपटने में चर्च की असमर्थता की आलोचना की गई है। कार्यालय का कहना है कि आरोपों की जांच अधूरी रही और कई मामलों में कानून का पालन नहीं किया गया और बाल कल्याण संस्थाओं को सूचना भी नहीं दी गई। मैडिगन ने कहा ''इस जांच के शुरूआती चरणों से पहले ही साफ हो चुका है कि कैथोलिक चर्च अपनी निगरानी नहीं कर सकता।''

### सीरिया में अमेरिकी सेना ने आतंकियों को हराया, जीत के बाद अमेरिका वापस आएगी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सीरिया में वर्षों से आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रही अमेरिकी सेना को अब घर वापस बुलाने का वक्त आ गया है। बुधवार को ट्विटर पर पोस्ट एक वीडियो संदेश में आईएस जिहादियों की हार की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा, ''हम जीत गए।'' उन्होंने कहा, ''हमने उन्हें हरा दिया है और उन्हें बुरी तरह हराया है। हमने जमीन वापस ले ली है। उन्होंने कहा, ''इसलिए हमारे लड़के, युवतियां, हमारे लोग.... वे सभी वापस आ रहे हैं।'' वाशिंगटन में सीरिया से 2000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की खबरों के बीच ट्रंप का यह संदेश आया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने इस पर अंतिम फैसला मंगलवार को लिया। वहीं, व्हाइट हाउस का कहना है कि सीरिया से सैनिकों को वापस बुलाने का ट्रंप का फैसला उनकी नीतियों के अनुरूप है क्योंकि युद्ध से जर्जर देश में अमेरिकी सैनिकों का मुख्य कार्य आईएस को हराना था। अमेरिकी सेना वहां कभी भी गृहयुद्ध के समाधान के लिए नहीं गई थी।

### अमेरिका उत्तर कोरिया के यात्रा प्रतिबंध की समीक्षा करेगा : अधिकारी

सियोल। ट्रंप प्रशासन के उत्तर कोरिया के विशेष दूत ने कहा कि वाशिंगटन इस देश में यात्रा पर लगे प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए इसकी समीक्षा कर रहा है ताकि मानवीय आवश्यकता वाली खेप यहां भेजी जा सके। यह परमाणु कूटनीति के गतिरोध को सुलझाने के प्रयास का हिस्सा है।

उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीफन बेगुन ने यह टिप्पणी दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद परमाणु वार्ता को लेकर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच इस साल जून में हुई शिखर वार्ता के बाद परमाणु वार्ता कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाई है। बेगुन ने कहा कि दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत इस बात को लेकर होगी कि कैसे साथ मिलकर उत्तर कोरिया से उस तरह से बातचीत की जाए जो पिछले 70 वर्षों से ज्यादा की शत्रुता को समाप्त करने में मदद दे।

# अमेरिका ने भारत और मालदीव के बीच संबंधों का स्वागत किया

**वाशिंगटन (एजेंसी)।**

ट्रंप प्रशासन ने भारत के मालदीव के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने का स्वागत किया है। अमेरिका का यह बयान भारत के उस फैसले के दो दिन बाद आया है जिसमें भारत ने चीन का बढ़ता कर्ज चुकाने की चुनौती का सामना कर रहे मालदीव को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। हाल ही में मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह तीन दिन के भारत दौरे पर थे।

इस दौरान सोलिह ने भारत को मालदीव का सबसे करीबी दोस्त और सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समुद्री सहयोग को लेकर एक-दूसरे की चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति सचेत रहने के लिये सहमति बनी थी।

दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के अमेरिका के उप सहायक विदेश मंत्री डेविड रैंज ने बुधवार को भारतीय पत्रकारों से कहा, 'हम भारत के मालदीव के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने के कदम का स्वागत करते हैं और हाल ही में राष्ट्रपति सोलिह की भारत यात्रा के दौरान हुई सकारात्मक घोषणाओं से अवगत हैं।' रैंज ने कहा कि भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में मालदीव की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर अमेरिका जैसा नजरिया रखता है और इस मुश्किल समय में सहयोग देने के महत्व को भी समझता है।

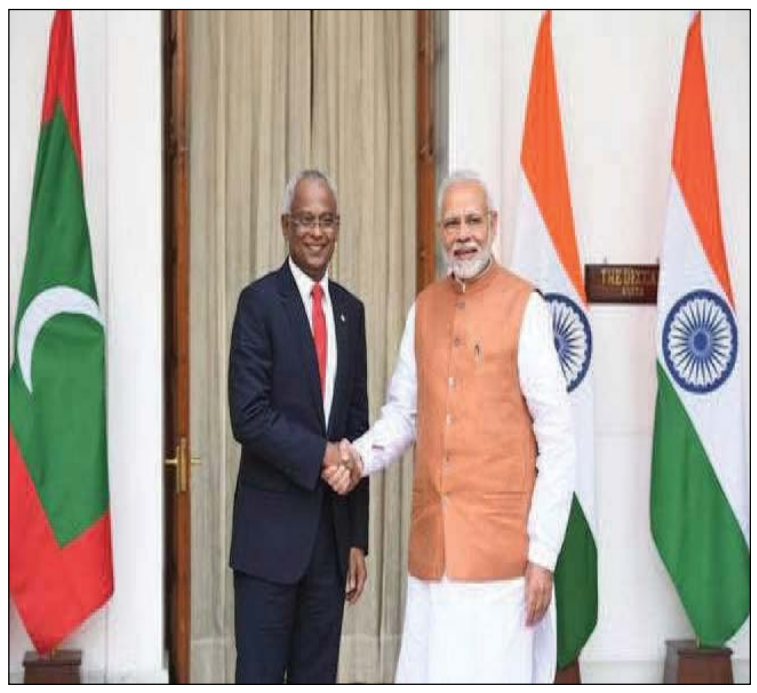

# अल्बानिया ने सुरक्षा कारणों से ईरानी राजनयिकों को निष्कासित किया

**तिराना।** अल्बानिया ने सुरक्षा कारणों से ईरान के दो राजनयिकों को निष्काषित कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने एक की पहचान राजदूत के रूप में की और कहा है कि इस जोड़े ने बाल्कान शहर में आतंकवादी हमलों की साजिश रची थी। अल्बानिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडलिरा प्रेंदी ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि इन राजनयिकों पर 'देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में संलिप्तता' का संदेह था। साथ ही उन्होंने बताया कि यह फैसला अन्य देशों के साथ परामर्श करने के बाद लिया गया। उन्होंने कूटनीतिज्ञों के नाम या उनके कथित अपराध की प्रकृति के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। बहरहाल, इस कदम का स्वागत करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने एक बयान में इन राजनियकों को, 'अल्बानिया में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने वाले दो ईरानी एजेंट' बताया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन ने भी इनमें से एक की पहचान राजदूत के तौर पर की।

# श्रीलंकाई प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के साथ कार्य जारी रखने को लेकर आशान्वित

**वाशिंगटन (एजेंसी)।**

अमेरिका ने कहा है कि वह पुनः बहाल किए गए श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ कार्य जारी रखने को लेकर आशान्वित है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने गत 26 अक्टूबर को विक्रमसिंघे को प्रधनमंत्री पद से विवादास्पद तरीके से बर्खास्त कर उनकी जगह पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। इस कदम से श्रीलंका में अभूतपूर्व संवैधानिक और राजनीतिक संकट पैदा हो गया था।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गत रविवार को सिरिसेना को विक्रमसिंघे को

प्रधानमंत्री के रूप में बहाल करना पड़ा। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि विक्रमसिंघे को बर्खास्त करने का सिरिसेना का कदम असंवैधानिक है। इसके साथ ही सांसदों ने विश्वासमत के दौरान विक्रमसिंघे के पक्ष में वोट डाला।

दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के अमेरिका के उप सहायक विदेश मंत्री डेविड रैंज ने भारतीय संवाददाताओं के एक समूह से बुधवार को कहा, ''हम श्रीलंका की अदालतों में दिखी लोकतांत्रिक, संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर खुश हैं, अंततः लोकतांत्रिक और संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए राजनीतिक संकट का समाधान हो गया। उन्होंने कहा, ''हम समान हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे और उनके मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति सिरिसेना के साथ भी कार्य जारी रखने को लेकर आशान्वित हैं।''

# हवाई केस में चीन ने तीसरे कनाडाई नागरिक को हिरासत में लिया

**टोरंटो (एजेंसी)।**

कनाडा की सरकार ने कहा है कि चीन ने तीसरे कनाडाई नागरिक को हिरासत में लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ऐसा लगता है कि तीसरी गिरफ्तारी अन्य दो की गिरफ्तारी से अलग है और वह दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के पक्षधर हैं। पहले दो मामले अमेरिका के लिए कनाडा में चीनी कंपनी के शीर्ष अधिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रतीत होते हैं। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके पास सूचना है कि चीन में तीसरे कनाडाई नागरिक को हिरासत में लिया गया है और दूतावास अधिकारी परिवार को सहायता मुहैया करा रहे हैं। ट्रूडो ने बुधवार को कहा कि यह सामान्य मामला प्रतीत होता है। इसमें अन्य दो की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोप नहीं लगाए गए हैं। संभवतः यह वीजा से जुड़ा कोई मामला हो सकता है। वर्षांत के अपने संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो ने कहा, ''हजारों की संख्या में कनाडाई हैं जो चीन में रहते हैं, वहां की यात्रा करते हैं और वहां काम करते हैं।''

उन्होंने कहा, 'यह नया मामला पुराने दोनों मामलों जैसा नहीं है।'' उन्होंने कहा कि अधिकारी और जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। यह पूछने पर कि क्या ट्रूडो इस संबंध में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी से हिरासत में लिए गए लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। ट्रूडो ने कहा कि इस बात को और बढ़ाने या बहुत कड़े शब्दों में राजनीतिक बयान देने से कई बार बात बिगड़ भी जाती है। मामले की शुरूआत कनाडा द्वारा चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी हुआवे की मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) मेंग वानझोऊ की गिरफ्तारी से हुई। कनाडा ने अमेरिका के अनुरोध पर एक दिसंबर को मेंग को गिरफ्तार किया था।

# अंतरिक्ष में 6 महीने बिताकर धरती पर लौटे तीन अंतरिक्ष यात्री

**मॉस्को (एजेंसी)।**

अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में छह महीने से अधिक समय गुजारने के बाद तीन अंतरिक्ष यात्री बृहस्पतिवार को धरती पर लौट आए. इन अंतरिक्ष यात्रियों में नासा की सेरेना ऑनन-चांसलर, रूस के सर्गेई रोकोयेव और जर्मनी के एलेक्जेंडर गर्स्ट शामिल हैं. इन सभी को लेकर रूसी सोयूज यान गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय समयानुसार पांच बजकर दो मिनट पर कजाकिस्तान में उतरा. अंतरिक्ष यात्रियों ने रेडियो पर कहा कि वे अच्छा महसूस कर रहे हैं.

तीनों यात्रियों ने अंतरिक्ष में 197 दिन बिताए. यह दो अंतरिक्ष यात्रियों सेरेना ऑनन-चांसलर और सर्गेई रोकोयेव का पहला जबकि गर्स्ट का दूसरा मिशन था. धरती पर उतरने के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआती चिकित्सकीय जांच की गई. अंतरिक्ष यात्रियों को अपने-अपने देश रवाना होने से पहले स्वागत के लिए जेजकजगान ले जाया जाएगा.

# चीनी विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत पर एक विधेयक को दिया कानून का रूप

**वाशिंगटन (एजेंसी)।**

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत पर एक विधेयक पर दस्तखत कर उसे कानून का रुप दे दिया है, जिससे चीन की त्यौरियां चढ़ सकती हैं. इस कानून से उन चीनी अधिकारियों पर वीजा पाबंदी लगाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जो अमेरिकी नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों को तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक गुरू दलाईलामा के गृह क्षेत्र (तिब्बत) में जाने की अनुमति नहीं देते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि तिब्बत जाने को इच्छुक सरकारी अधिकारियों, संवाददाताओं और पर्यटकों समेत अमेरिकी नागरिकों के अनुरोध को नियमित रुप से ठुकरा दिया जाता है. वहीं, जो कुछ लोग वहां चले भी जाते हैं उन्हें नियंत्रित आधिकारिक यात्रा पर रहने के लिए बाध्य किया जाता है. इस तरह, तिब्बती लोगों की वास्तविक दशा उनसे छिपायी जाती है.

तिब्बत मूल के अमेरिकियों के अनुसार उनके लिए स्थिति बदतर है क्योंकि उन्हें अपने पुरखों की जमीन पर जाने और वहां अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलने दिया जाता है.

**चीन ने अमेरिका से कानून नहीं बनाने के लिए कहा था**

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब चीन ने इस संबंध में कानून पारित करने को लेकर अमेरिका से सख्त राजनयिक प्रतिरोध जताया था. चीन ने अमेरिका से इस सिलसिले में कानून नहीं बनाने को कहा था.

दरअसल, चीन का कहना है कि तिब्बत सदियों से उसका हिस्सा रहा है. दलाईलामा चीनी शासन के खिलाफ विफल विद्रोह के बाद 1959 में भारत पलायन कर गये थे.

व्हाईट हाऊस ने कहा है कि ट्रंप ने 'रेसीप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट ऑफ 2018' पर दस्तखत कर उसे कानून का रुप दे दिया है. यह कानून अमेरिका के राजनयिकों, अधिकारियों, पत्रकारों और अन्य को तिब्बत में जाने का मार्ग प्रशस्त करता है. इस विधेयक को इससे पहले सीनेट और प्रतिनिधि सभा ने मंजूरी दे दी थी.

# यूएस पहले अपने खतरे को खत्म करे, वर्ना नहीं होगा परमाणु निरस्त्रीकरण : उत्तर कोरिया की धमकी

**सियोल (एजेंसी)।**

उत्तर कोरिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर अमेरिका अपने परमाणु खतरे को पहले समाप्त नहीं करता है तो उत्तर कोरिया एकतरफा अपना परमाणु निरस्त्रीकरण नहीं करेगा. सरकारी कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी के माध्यम से यह बयान ऐसे वक्त आया है जब परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है.

बृहस्पतिवार को जारी बयान में उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर अपना पुराना रुख दोहराया और वाशिंगटन पर सिंगापुर में हुए समझौते के संबंध में सभी को गुमराह करने का आरोप लगाया. बयान में कहा गया है कि अमेरिका अब कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के अर्थ को सही तरीके से समझे और वह तुरंत यहां का भूगोल पढ़े.

इसमें कहा गया है कि जब हम कोरियाई प्रायद्वीप की बात करते हैं तो इसमें हमारे गणतंत्र के अलावा पूरा क्षेत्र (दक्षिण कोरिया भी) शामिल होता है जहां अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार सहित सेना तैनात कर रखी है. जब हम कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के परमाणु खतरे को समाप्त करने की बात होती है. उसमें बात सिर्फ दक्षिण या उत्तर कोरिया की नहीं, बल्कि कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्रों की भी होती है.

इससे कुछ दिन पहले अमेरिका मीडिया ने दावा किया था कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन के बाद से प्योंगयांग ने अपने एक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रतिष्ठान का विस्तार किया है. यह बात सीएनएन ने चार दिसंबर को उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर कही.

सीएनएन के अनुसार, उत्तर कोरिया ने पर्वतीय क्षेत्र स्थित अपने यीओंगजेओ-डोंग मिसाइल प्रतिष्ठान को उन्नत किया है और एक अन्य प्रतिष्ठान का निर्माण किया है जो पूर्व में सार्वजनिक रूप से पहचान में नहीं आया था. इस पर पेंटागन ने एक बयान में कहा, ''हम उत्तर कोरिया पर करीब से नजर रखते हैं, लेकिन हम खुफिया जानकारी पर चर्चा नहीं कर सकते.''

# यूरोपीय संघ ने हजारों राजनयिक संदेशों की हैकिंग मामले की जांच शुरू की

**ब्रसेल्स, (एजेंसी)।**

यूरोपीय संघ ने संदिग्ध चीनी सैन्य

हैकर्स द्वारा हजारों संवेदनशील राजनयिक संदेशों की हैकिंग के तत्काल बाद मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी 'एरिया1 सिक्योरिटी' ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक इकाई ने सरकारी आदेशों पर अमल करते हुए यूरोपीय संघ द्वारा अपनी विदेशी नीति के समन्वय के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सुरक्षित संचार नेटवर्क में सेंध लगाई।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ संदेश प्रकाशित किए हैं जो दुनियाभर में यूरोपीय संघ के राजनयिक मिशनों से भेजे गए हैं। इन संदेशों में चीन, रूस और ईरान की गतिविधियों को लेकर चिंता प्रकट करने के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। यह वाकया 2010 में विकीलीक्स द्वारा अमेरिकी विदेश विभाग के तमाम संदेशों को सार्वजनिक किए जाने की घटना याद दिलाती है। हालांकि यूरोपीय संघ का मामला उसके मुकाबले बहुत छोटा है और इसमें उससे कम गोपनीय संदेश शामिल हैं। दस्तावेजों का आकलन करने में सक्षम एरिया 1 ने कहा कि हमलों में यूरोपीय संघ, अमेरिका और अमेरिका के एएफएल-सीआईओ मजदूर संघ को निशाना बनाया गया था। ईयू के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है।

# उधना जोन क्षेत्र में नगर सेवकों की मेहरबानी से फल फूल रहा अवैध कब्जे का धन्धा

उधना रोड़ नं. 4

लक्ष्मीनारायण बी.आर.सी

120 फुट रोड़ बमरौली रोड़, शिव शक्ति कॉम्पलैक्ष

सूरत। बहुजने सुखाय, बहुजन हिताय के सिद्धांत पर चलने का दावा कनरे वाली सूरत महानगर पालिका के अधिकारी नगर सेवाकों की दखल तथा दबाव के चलते अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे है।

इन अधिकारियों को नगर सेवकों के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। नगर सेवकों की धौंस व दखल अंदाजी का समाधान नहीं कर पा रहे है। उधना जोन क्षेत्र स्थित पांडेसरा इलाके में सरकारी जमीनों अथवा कामन ओपन प्लाट पर खुलेआम कब्जा कर अतिक्रमण किया जा रहा है। क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण तथा अवैध कब्जे की शिकायत जब संबंधित अधिकारियों से की जाती है तो अधिकारियों को डरा धमा कर अवैध कब्जा हटाने से रोका जाते ह। यदि कोई अधिकारी ईमानदारी दिखाने की कोशिश करता है तो क्षेत्र के नगर सेवकों द्वारा पहले धमकाया जाता है और न मानने पर उसे झूठे आरोपों में फंसा कर विभागिय जांच कराने तथा निलम्बित कराने की धमकी दी जाती है। ऐसे में अधिकारी न तो ठीक से काम कर पाता है और न सही ठंग से अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर पाता है। शहर के पांडेसरा क्षेत्र में स्थित शिवशक्ति शांपिंग सेंटर के बगल में मनपा की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। 120 फूट बमरौली रोड़ पर एच.पी पेट्रोल पम्प के सामने महानगर पालिका द्वारा निर्मित शिव शक्ति शापिंग सेंटर की दुकान नं. 1 के पास मार्जिन की जगह में शापिंग सेंटर की पीछे भींडभजन इंडस्ट्रीयल सोसायटी में गैरज चलाने वाले ने अवैध कब्जा कर रखा है। जिससे यहां से आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भीडभंजन इंडस्ट्रीयल सोसायटी के प्लाट नं. 143 में हिंदुस्तान गैरेज इंजीनियरिंग के मालिक द्वारा इस जगह पर भारी मशीनरी रखकर कब्जा कर लिया गया है। पहले इस जगह पर महानगर पालिका की तरफ से तार फेसिंग की गई थी। जिसे हिन्दुस्तान गैरेज के मालिक ने नगर सेवक की मदद से तार फेसिंग काटकर इसमें कब्जा कर लिया है। स्थानीय दुकानदारों तथा समाज सेवियों द्वारा जब इसकी शिकायत मनपा के अधिारियों से की जाती है तो अधिकारी तो आते है परन्तु बिना कार्रवाई वापस लौट जाते है। इन अधिकारियों पर यहां के नगर सेवक का इतना दबाव है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते है। नाम न बताने की शर्त पर उधना जोन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया की स्थानीय नगर सेवक की मर्जी के खिलाफ जाकर यदि हम कार्रवआई करते है तो उसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ता है। नगर सेवकों की दबंगई तथ धौंस के आगे हमारी एक नहीं चलती। ऐसे में सवाल यह उठता है कि नगर सेवक का काम नगर जनों के हितों की रक्षा के लिए काम करना है तो ये अपने हितों की रक्षा तथा लाभ के लिए कैसे काम कर सकते है। महानग पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भाजपा के नगर सेवक सत्ता के मद में इतना चुर है कि उन्हें अपने दायित्वों का बोध तक नहीं है। शहर में विपक्ष के कमजोर होने से नगर सेवक मनमानी तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने चहेतों के अवैध कब्जों को खाली कराने से रोक रहे है। सत्ता के मद में नगर सेवक शायद यह भूल जा रहे है कि फिर से जनता के दरबार में जाना है ये नगर सेवक ज्यादातर शहर के श्रमजीवी क्षेत्रों में अपनी दुकाने चलाते है जहां इनकी दादागिरी चलती है और इनके विरुद्ध किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे में शहर के महापौर, उपमहापौर, तथा विविध समिति के चेयरमैन को भी अपने क्षेत्र के निरंकुश नगर सेवकों पर अंकुश लगानी चाहिए। जिससे पार्टी के शाख को बचाया जा सके।

### ईमानदारी से कर्त्तव्य निभाना पड़ा महंगा

# सहायक कर्मचारी को मिला निलम्बन का आदेश

सूरत। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ देश व्यापी मुहिम चला रहे है। वहीं देश में कुछ ऐस भ्रष्ट अधिकारी है जो ईमानदारी से अपने कर्त्तवयों का पालन करने वाले कर्मचारी का नौकरी से निकाल कर यह साबित करने में लगे है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता।

इस तरह का एक मामला सूरत शहर के बेस्ट जोन में प्रकाश में आया है। जिसमें वेस्ट जोन में टोक्निकल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी को ईमानदारी दिखाने पर डेप्युटी म्युनिसिपल कमीश्नर द्वारा निलम्बित कर दिया गया। निलम्बित कर्मचारी जीगर कुमार के नायक की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने सहज सुपर स्टोर के बगल में पान का गल्ला चलाने वाले नागेंद्र ओमकारनाथ शुक्ल का गल्ला उठवाकर दबान खाता के डिपो में जमा करा दिया था। जिसको वापस लेने के लिए ओमकार नाथ शुक्ल ने जीगर कुमानर नायक से मोबाईल पर सम्पर्क किया। जिसपर जीगर ने गल्ला वापस करने से इनकार कर दिया। जिसकी शिकायत ओमकार नाथ शुक्ल ने उच्च अधिकारियों से की। अपनी शिकायत में ओमकारनाथ ने बताया कि मैने जीगर को मोबईल पर कहा कि जुर्माना भरकर में अपना गल्ला छुड़ाना चाहता हुँ। जिसपर जीगर भड़क गए और आली गलौज करने लगे। जीगर ने ओमकार नाथ की लारी को तोड़देने तथा शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी देने के साथ डेप्युटी मेय का नाम लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे।

ओमकारनाथ की शिकायत पर डेप्युटी कमीश्नर ने विभागीय जांच के बार सहायक कर्मचारी जीगर को निलम्बित कर दिया। जीगर को दिए निलम्बन पत्र में कहा गया है कि वेस्ट जोन में असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत जीगर कुमार जे. नायक कर्मचारी संख्या 408 41 को इस लिए निलम्बित किया जाता है कि उन्होंने गुजरात राज्य सेवा नियम 1971 के तहत काम न करते हुए अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया है। जिसकी वजह से महानगर पालिका की नौकरी से फर्ज मुक्त किया जाता है। निलम्बन पत्र में यह भी कहा गया है कि अनुमति के बिना शहर छोड़ कर कही बाहर नहीं जा रकते। निलम्बन के दौरान उन्हें प्रत्येक महीने निर्वहन भत्ता लेने से पहले असिस्टेंट कमीश्नर वेस्ट जोन के सामने पेश होना पड़ेगा। साथ ही लिखित में देना पड़ेगा कि इस बीच मैने कोई प्रइवेट नौकरी या को व्यवसाय नहीं किया है।

डेप्युटी कमीश्नर की इस कार्रवाई को लेकर मनपा कर्मचारियों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ सहर के तमाम समाजसेवियों तथा आरटीआई कार्यकर्त्ताओं द्वारा आए दिन यह कहा जाता है कि तमाम सबूत तथा साक्ष्यों के बावजूद मनपा अधिकारी भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते वहीं मात्र एक पान के गल्लेवाले की शिकायत डेप्युटी कमीश्नर द्वारा इतना बड़ा कदम उठाए जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो दबान खाता द्वारा कार्रवाई के दौरान उठाए गए सामान को 21 दिन तक वापस नहीं किया जा सकता। ऐसे में शिकायत कर्ता ने दूसरे दिन ही जुर्माना भर कर लारी वापन लेने की बात की। जिसपर संबंधित कर्मचारी ने मना कर दिया। मात्र इतनी सी बात पर सहायक कर्मचारी के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई हजम नहीं हो रही है।

अगर जीगर ने ओमकारनाथ को धमकी दी थी तो इसकी शिकायत पुलिस में की जानी चाहिए थी जो नहीं किया गया। जो कार्रवाई पुलिस में दर्ज करानी चाहिए वह विभाग में किया गया। निलम्बन की इस कार्रवाई को लेकर विभाग के अधिकारियों की मनशा पर सवाल उठने लाजमी है।

# मार्केट के व्यापारी से 2.50 लाख की ठगी

सूरत। शहर के रिंग रोड़ स्थित कोहिनूर माके4ट की एक दुकान से अज्ञात चोर 2.5 लाख की चोरी कर फरार हो गया।

प्राप्त जानकारी अनुसार 19 दिसंबर की शाम 7 बजे के करीब चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अज्ञात चोरों ने दुकान की खिड़की का ग्रील तोडकर अन्दर घुस गए तथा दुकान की काउंटर में रखे 2.5 लाख रुपये चुराकर भाग गए। दुकान के मालिक राधाकृष्ण बाबूलाल प्रजापति ने सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

सूरत टेक्सटाईल मार्केट में आए दिन चोरी के मामले होते रहते है जिसमें ज्यादातर घटनाएं बाहर से सूरत में खरीदारी के लिए आने वाले व्यापरियों के साथ होत हैहै। ज्यादातर मामलों में शिकायत तक दर्ज नहीं कराई जाती है। जिससे घटनाएं प्रकाश में नहीं आती। सूरत का कपड़ा मार्केट एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है यहां न केवल भारत के विभिन्न राज्यों से खरीदारी करने आने वाले व्यापारियों के साथ चोरी की घटनाएं होती है बल्कि विदेशी व्यापारी भी इसका शिकार बनते है।

## अलकापुरी ब्रिज पर बाईक फिसलने से चैनल के कैमरामैन की मौत

सूरत। शहर के आश्विनी कुमार रोड़ स्थित अलकापुरी फलाई ओवर ब्रिज पर बुधवार की रात बाईक फिसल जाने से प्रेस चैनल के कैमरामैन की मौत हो गई। हिन्द टी.वी के पूर्व कैमरा मैन अल्कापुरी फ्लाई ओवर ब्रिज से बाईक द्वारा जा रहे थे तभी अचानक बाईक स्लीप हो जाने से कैमरामैन निकुज के सिर में गंभीर चोटे आई। जिससे निकुंज की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

सूरत। सूरत महानगर पालिका द्वारा गुरुवार को स्वामी विवेकानंद ओडिटोरियम वराछा में आयोजित लगन गीत प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 20 दिसंबर को ओयजित इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विविध समितियों के अध्यक्षों, नगर सेवकों के अलावा अधिकारी गण उपस्थित रहे।

# 261 कन्याओं का सामूहिक विवाह 23 दिसंबर को

सूरत। पिता की छत्रछाया खो चुकी कन्याओं का हर साल विवाह कराने वाले पी.पी. सवाणी ग्रुप तथा मोवलिया परिवार की तरफ से 23 दिसंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में 261 कन्याओं के विवाह का सम्पूर्ण खर्चा तथा नवदम्पत्ति के गृहस्त जीवन के लिए सभी आवश्यक समाग्रिया इन पवािरों द्वारा दिया जाएगा।

विदित है कि पिता की छत्रछाया से महरुम हो चुकी कन्याओं का विवाह हर साल पी.पी. सवाणी ग्रुप की तरफ से कराया जाता है। जिसके लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। शादी के बाद आजीवन इस परिवार द्वारा पिता की जिम्मेदारियां निभाई जाती है। पिछले 2 वर्षों से पी.पी. सवाणी परिवार के साथ बटुकभाई मोवलिया का परिवार भी इस कार्य में सहभागी बनता आ रहा है। पी.पी. सवाणई ग्रुप तथा मोवलिया परिवार द्वारा इस साल 261 कन्याओं के विवाह का आयोजन किया गया है। 23 दिसंबर 2018, रविार को हने वाला भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन पी.पी. सवाणी चैतन्य विद्या संकुल अब्रमा, सूरत में होगा।

सामूहिक विवाह समारोह के विषय में जानकारी देते हुए पत्रकार परिषद में पी.पी. सवाणई ग्रुप के महेश भाई सवाणी तथा मोवलिया परिवार के बटुकभाई मोवालिया ने बताया कि इस वर्ष सामूहिक विवाह में जिन 261 कन्याओं की शादी होगी उसमें से 6 मुस्लिम लड़कियां, 3 इसाई लड़कियों की भी शादी भी उनकी रीती रिवाज एवं परम्परा से कारई जाएगी।

इस सामूहिक विवाह में किसी भी धर्म व जाति का भेदभाव किए बिना विधवा बहनों की लड़कियों कीशादी कराई जाएगी। इस समारोह की सबसे पड़ी खासियत यह होगी की इसमें एक तरफ जहां वैदिक रीती रिवाज से हिन्दु कन्याओं का विवाह होगा वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कन्याओं के विवाह में निकाह पढ़ा जाएगा। इस समारोह में देश भर से 50 से अधिक यशस्वी महानुभावों के साथ विविध धर्मों के संत एवं महंत शामिल होंगे। कार्यक्र में 300 से अधिक आई.एस.आई पी.एस. तथा कार्पोरेट जगत के 50 से अधिक हस्तियां शामिल होंगी।

# टैम्पों ने बाईक को मारी टक्कर, बाईक सवार की मौत

सूरत। कामरेज-नवागाम उद्योगनगर के पास अज्ञात टेम्पो चालक द्वारा बाईक सवार को टक्कर मारने से गटर के काम के लिए ले जा रहा सारिया बाईक सवार के सिर में घुस गए। जिससे बाईक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद टैम्पों चालक टैम्पों लेकर फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कामरेज के वाव गांव के देसाई फलिया का रहने वाला महेन्द्रभाई लाडे द्वारा कामरेज पुलिस में दर्ज कारई गई शिकायत के अनुसार कामरेज-नवागाम उद्योगनगर के पास एक अज्ञात टैम्पों चालक ने जी जे 05 के ए 4475 नम्बर की बाईक पर सवार चालक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाईक सवार के सिर में गटर की लोहे की सरिया घुस जाने से बुरी तरह घायल हो गया। जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com ( subject to surat jurisdiction)